NPCI

IMPS IMMEDIATE PAYMENT SERVICE

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को तकनीक आधारित 2013 उत्पाद- आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) और इमीडिएट पेमेंट सर्विस (आईएमपीएस) बनाने के लिए वित्तीय समावेशन क्षेत्र का वर्ष 2013 का प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड हाल ही में प्रदान किया गया. वर्ष 2010 में महज सात लोगों के साथ शुरू किए गए इस निगम के कर्मचारियों की संख्या अब 435 के पार पहुंच चुकी है और इसने देश में खुदरा भुगतान की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अनेक विशिष्ट उत्पाद तैयार किए हैं. यहां हम एनपीसीआई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी श्री ए.पी. होता से बातचीत के अंश दे रहे हैं:

बीते सालों के दौरान एनपीसीआई ने कितनी तेज तरक्की की है? एनपीसीआई का विजन क्या है?

जब हमने अपना महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करते हुए कहा था कि हम 2020 तक अपनी कम से कम एक भुगतान सेवा को हर भारतीय तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम जानते थे कि यह काम आसान नहीं होगा. महज चार साल से कुछ अधिक वक्त में हम एक ऐसे संस्थान के रूप में विकसित हुए हैं जो रोजाना एक करोड़ से अधिक लेनदेन करता है. इस काम में 200 से अधिक एनएफएस (नेशनल फाइनैंशियल स्विच) सदस्य बैंक मदद करते हैं. इसके अलावा 100 से अधिक बैंक रुपे कार्ड जारी करते हैं जिन्हें 3.5 लाख से अधिक पीओएस केंद्रों में स्वीकार किया जाता है. इतना ही नहीं यह आंकड़ा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. इसके अलावा 2.5 करोड़ उपभोक्ता आधार मैपर पर तथा 5.1 करोड़ ग्राहक एमएमआईडी तथा अन्य योजनाओं से जुड़े हैं. हर भारतीय तक पहुंच बनाने के लिए अब हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि हर रोज 30 करोड़ तक लेनदेन किए जा सकें.

आप देश के लोगों को विश्वस्तरीय खुदरा भुगतान सुविधा प्रदान करने के लिए किस तरह के प्रयास कर रहे हैं?

हम देश में भुगतान प्रदान करने वाली प्रमुख व्यवस्था के रूप में अपनी जिम्मेदारी को भलीभांति समझते हैं और हम मजबूत तकनीक के जरिये इस काम को अंजाम देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इससे न केवल हमारी व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि भुगतान की प्रक्रिया भी आसान होगी और हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान लाएगी. हमारा ध्यान खुदरा भुगतान पर है. हम चेक, डेबिट कार्ड, एटीएम लेनदेन, कम पैसों के लेनदेन और आधार आधारित इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तांतरण संबंधी लेनदेन आदि के क्षेत्र में काम करते हैं.

एनएफएस, आईएमपीएस और रुपे का विकास किस गति से हो रहा है और इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

नेशनल फाइनैंशियल स्विच का इस्तेमाल बैंकों के आपसी लेनदेन के लिए किया जाता है. पहले इसके औसत दैनिक लेनेदेन की संख्या 18 लाख थी जो एनपीसीआई की शुरुआत के बाद 70 लाख प्रतिदिन हो गई है. हमने अपनी व्यवस्था में सुधार कर इसे रोजाना दो करोड़ लेनदेन के सक्षम बनाया है. इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी आईएमपीएस नकदी लेनदेन की व्यवस्था है जो रिजर्व बैंक की मुद्रा स्थानांतरण व्यवस्था आरटीजीएस और एनईएफटी का विकल्प है. आईएमपीएस की खासियत यह है कि यह बहुत तेज गति से काम करती है और यह सप्ताह के हर दिन 24 घंटे उपलब्ध है. इसमें लेनदेन का काम ग्राहक खुद अपने मोबाइल अथवा इंटरनेट के जरिये करता है. हमने एक मोबाइल चैनल सर्विस के रूप में शुरुआत की थी लेकिन अब यह चैनल रहित सेवा बन चुकी है. रुपे को एनपीसीआई ने एक घरेलू भुगतान कार्ड के रूप में शुरू किया है और यह बैंकों द्वारा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कार्ड जारी किए जाने का विकल्प है. रुपे मुख्य रूप से घरेलू बाजार पर केंद्रित है लेकिन हमने इससे संबंधित अंतरराष्ट्रीय पेशकश भी की हैं जहां हमने रुपे कार्ड को चिप और पिन से जोड़ा है.

RuPay

आधार आधारित भुगतान तेजी से बड़ा आकार ले रहा है. आप इस क्षेत्र में क्या अवसर देख रहे हैं?

हम आधार को एक वित्तीय पते के रूप में देख रहे हैं. अगर पैसा किसी आधार नंबर को भेजा गया तो फिर उस आधार अंक के सहारे यह खोजा जाता है कि वह किस बैंक तथा किस खाते से जुड़ा हुआ है. इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हमने आधार पेमेंट ब्रिज की शुरुआत की है. यह पेमेंट ब्रिज कई राज्य सरकारों, केंद्र सरकार और अब एलपीजी गैस सब्सिडी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. इस योजना की शुरुआत एक जनवरी को बहुत छोटी संख्या के साथ हुई थी लेकिन अब इसमें तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. पिछले महीने हमने 20 लाख लेनदेन किए. दूसरा हिस्सा आधार को कार्ड के जरिये प्रमाणन के रूप में इस्तेमाल करने से जुड़ा है. जिस तरह हम एटीएम पर चार अंकों की पिन का इस्तेमाल करके खुद को प्रमाणित करते हैं, आधार के मामले में हम अपनी पहचान बायोमेट्रिक हस्ताक्षर के जरिये पेश कर सकते हैं.